

२० = 15 मई 1971

रजिस्ट्री सं० डी-222

REGISTERED No. D-222

**भारत का राजपत्र**  
**The Gazette of India**  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 19] नई दिल्ली, शनिवार, मई 15, 1971 (वैशाख 25, 1893)

No. 19] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 15, 1971 (VAISAKHA 25, 1893)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

घोषितम्

(NOTICE)

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 8 फरवरी 1971 तक प्रकाशित किये गये हैं :—

The undermentioned Gazettes of India Extraordinary were published up to 8 February 1971 :—

अंक (Issue No.)	संख्या और तिथि (No. and Date)	द्वारा जारी किया गया (Issued by)	विषय (Subject)
1	2	3	4

शून्य  
—NIL—

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां प्रकाशन प्रबन्धक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांग-पत्र भेजने पर भेज दी जाएंगी।  
मांग-पत्र प्रबन्धक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तिथि से दस दिन के भीतर पहुँच जाने चाहिए।

Copies of the Gazette Extraordinary mentioned above will be supplied on indent to the Manager of Publications, Civil Lines, Delhi. Indents should be submitted so as to reach the Manager within ten days of the date of issue of these Gazettes.

61GI/71

(441)

## विषय-सूची

भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . . . . .	पृष्ठ 441	भाग II—खंड 3—उप-खंड (ii)— रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं . . . . .	पृष्ठ 2337
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मन्त्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . . . . .	687	भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश . . . . .	341
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . . . . .		भाग III—खंड 1—महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं . . . . .	599
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं . . . . .	555	भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिसें . . . . .	171
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम . . . . .	—	भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं . . . . .	65
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्टें . . . . .	—	भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिसें शामिल हैं . . . . .	1271
भाग II—खंड 3—उप-खंड (i)—(रक्षा मन्त्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं) . . . . .	1869	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिसें . . . . .	97
		पूरक संख्या 19— 1 मई 1971 को समाप्त होने वाले सप्ताह की महामारी सम्बन्धी साप्ताहिक रिपोर्टें 10 अप्रैल 1971 को समाप्त होने वाले सप्ताह के दौरान भारत में 30,000 तथा उससे अधिक आबादी के शहरों में जन्म तथा बड़ी बीमारियों से हुई मृत्यु सम्बन्धी आंकड़े . . . . .	755 723

  

PART I—SECTION. 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court . . . . .	441	PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) . . . . .	2337
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government, Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court . . . . .	687	PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence . . . . .	341
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence . . . . .		PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India . . . . .	599
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence . . . . .	555	PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta . . . . .	171
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations . . . . .	—	PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners . . . . .	65
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills . . . . .	—	PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies . . . . .	1271
PART II—SECTION 3.—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories) . . . . .	1869	PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies . . . . .	97
		SUPPLEMENT NO. 19 Weekly Epidemiological Reports for weeks ending 1st May 1971 . . . . .	755
		Births and Deaths from Principal diseases in towns with a population of 30,000 and over in India during week ending 10th April 1971 . . . . .	723

## भाग I—खण्ड 1

## (PART I—SECTION 1)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

## योजना आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 23 अप्रैल 1971

## संकल्प

## अतिरिक्त उत्पादन शुल्क हेतु स्थायी पुनरीक्षण समिति

सं० एफ० 3/5/70-सी० डी० एन०:—पांचवे वित्त आयोग ने यह सिफारिश की है कि जब तक भारत सरकार इस विषय पर पुनः राज्य सरकारों से विचार-विमर्श करके वर्तमान व्यवस्थाओं में उपयुक्त परिवर्तन करके सामान्यतः इसे जारी रखने के समझौते पर न पहुंच जाए तब तक यह बांछनीय नहीं है कि चीनी, तम्बाकू तथा मिल-निर्मित वस्त्रों पर राज्य विन्ती कर के स्थान पर लगाये गये अतिरिक्त उत्पादन करों के संबंध में वर्तमान व्यवस्थाओं को बनाए रखा जाय इस सिफारिश का अनुसरण करते हुए, इस विषय को, राज्य सरकारों, संघीय क्षेत्रों तथा संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों के अधिकारियों से विचार-विमर्श के पश्चात् 28 दिसम्बर, 1970 को दिल्ली में हुई बैठक में, राष्ट्रीय विकास परिषद् समिति के सामने प्रस्तुत किया गया था। समिति, अतिरिक्त उत्पादन शुल्क से प्राप्त राजस्व को लोक प्रदान करने हेतु नयी व्यवस्था बनाने के विषय में सहमत हो गई थी। इसने यह भी सिफारिश की कि अतिरिक्त उत्पादन शुल्क की कार्यप्रणाली के समय-समय पर पुनरीक्षण तथा इसके संबंध में नयी व्यवस्थाओं में सुधार हेतु सुझाव देने के लिए योजना आयोग द्वारा एक स्थायी पुनरीक्षण समिति की स्थापना की जानी चाहिए।

2. अतएव योजना आयोग ने एक स्थायी पुनरीक्षण समिति नियुक्त करने का निर्णय किया है। इस समिति में निम्नलिखित व्यक्तियों को शामिल किया जाएगा :—

- |   |        |
|---|--------|
| (1) आर्थिक सलाहकार, योजना आयोग  | संयोजक |
| (2) सदस्य (सीमाशुल्क) उत्पादन शुल्क तथा चुंगी का केन्द्रीय बोर्ड, वित्त मंत्रालय, राजस्व तथा बीमा विभाग | सदस्य  |
| (3) आर्थिक सलाहकार, वित्त मंत्रालय आर्थिक कार्य विभाग   | सदस्य  |
| (4) वित्त आयुक्त अथवा सचिव, जो उस समय, प्रत्येक राज्य में बिन्ती कर का इंचार्ज हो।                      | सदस्य  |

3. समिति के समक्ष विचारार्थ विषय इस प्रकार हैं:—

अतिरिक्त उत्पादन शुल्क हेतु बनाई गई नयी व्यवस्था की कार्यप्रणाली का समग्र रूप से पुनरीक्षण तथा इसके विकास के लिए आवश्यक सिफारिशें करना।

4. स्थायी पुनरीक्षण समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

5. स्थायी पुनरीक्षण समिति की बैठक कम से कम वर्ष में एक बार हुआ करेगी।

## आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों, संघशासित क्षेत्रों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, प्रधानमंत्री सचिवालय, राष्ट्रपति के सचिव तथा उपराष्ट्रपति के सचिव को भेज दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाय।

अशोक मित्र सचिव

## औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय

## (औद्योगिक विकास विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 30 अप्रैल 1971

## संकल्प

सं० एस० एस० आई० (बी०)—10(3)/68—अपने कार्यालय ज्ञापन सं० एस० एस० आई० (बी०)—10(3)/68 दिनांक 23 सितम्बर 1968 में भारत सरकार ने भूतपूर्व औद्योगिक विकास, आंतरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) में आविष्कार संवर्धन बोर्ड की गतिविधियों की संवीक्षा करने तथा मूल्यांकन करने के लिए और यह सुनिश्चय करने के लिए कि बोर्ड ने अपने उद्देश्यों के संवर्धन में जिसके लिए इसकी स्थापना की गई थी, कितनी सहायता दी है तथा बोर्ड के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विशेषकर लघु क्षेत्र पर बल देते हुए, आवश्यक अम्युपायों की सिफारिश करने हेतु, श्री एन० जे० कामथ, संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी।

2. समिति ने 16-4-70 को प्रस्तुत किये गये अपने प्रतिवेदन में अनेक सिफारिशें की हैं जिनमें से विशेष महत्वपूर्ण निम्नलिखित हैं :—

- (1) आविष्कार संवर्धन बोर्ड औद्योगिक विकास तथा आन्तरिक व्यापार मंत्रालय के नियंत्रण के अधीन स्वायत्तशासी संगठन के रूप में कार्य करता रहे।

- (2) बोर्ड के कार्य को चलाने के लिए वित्तीय तथा कार्य-संरहण संबंधी मामलों पर अधिक नियंत्रण के सुनिश्चय हेतु प्रशासनिक मामलों में कार्यकारी निदेशक को मार्गप्रदर्शन करने के लिए बोर्ड के उपाध्यक्ष को (जो औद्योगिक विकास मंत्रालय का प्रतिनिधि भी है) शक्तियां प्रत्यायोजित की जायें।
- (3) कार्यकारी निदेशक को परामर्श देने के लिए बोर्ड के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में अल्प सदस्यों की कार्यकारी समिति गठित की जाये।
- (4) ग्रामीण समस्याओं के संदर्भ में आविष्कार संवर्धन बोर्ड के कार्यों का पुनर्वीकरण किया जाये। बोर्ड द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सहायता तथा पुरस्कार स्वतंत्र आविष्कर्ताओं, कारीगरों तथा तकनीशियनों को अधिक मात्रा में प्राप्त होने चाहिए।
- (5) आविष्कारकों के सहायतार्थ पेटेंट विशिष्टियां प्राप्त करने के लिए बोर्ड द्वारा एक सुसज्जित पेटेंट सूचना केन्द्र चालू किया जाना चाहिए।

3. सावधानी से विचार करने के पश्चात् तथा प्रतिवेदन के प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त बोर्ड के कार्यों में पहले से ही हुए परिवर्तनों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने समिति द्वारा की गई सभी सिफारिशों को निम्नलिखित शर्तों के अधीन स्वीकार कर लिया है :—

(I) सिफारिश संख्या 2.

- (क) अध्यक्ष यदि आवश्यक समझें तो बोर्ड के सुचारु रूप से कार्य संचालन के लिए जैसा भी अभीष्ट और आवश्यक है, उपाध्यक्ष को प्रशासनिक शक्तियां प्रत्यायोजित कर सकते हैं।
- (ख) सरकार की यह भी इच्छा है कि आविष्कार संवर्धन बोर्ड द्वारा दी जाने वाली सहायता से होने वाले आविष्कारों पर बोर्ड द्वारा अधिकाधिक ध्यान दिया जाये। इसके लिए बोर्ड को सरकार के अन्य संबंधित अभिकरणों के साथ निकट सहयोग में कार्य करना चाहिए।

4. सरकार यह भी चाहती है कि आविष्कार संवर्धन बोर्ड के कार्यों का गहन अध्ययन तथा उनके मूल्यांकन करने में श्री एन० जे० कामथ की अध्यक्षता में समिति द्वारा किये गये कार्य की सराहना को रिकार्ड में रखा जाये।

**आदेश**

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति सभी संबंधितों को भेजी जाये।

सर्व साधारण की सूचना के लिए यह भी आदेश दिया जाता है कि संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

बी० बी० लाल सचिव

नई दिल्ली, दिनांक अप्रैल 1971

सं० एस० एस० आई० (ए)—17(3)/70—औद्योगिक विकास तथा आंतरिक व्यापार मंत्रालय के संकल्प संख्या एस० एस० आई० (ए)—17(3)/70 दिनांक 25 अगस्त 1970 में, जिसके अधीन लघु उद्योग बोर्ड का पुनर्गठन किया गया था, बोर्ड के सदस्यों की सूची में निम्नलिखित संशोधन किया जाये :—

के स्थान पर :—

56. अध्यक्ष,

राजस्थान इण्डस्ट्रियल एस्टेट मैन्युफैक्चरर्स एसोशियेशन,  
40, इण्डस्ट्रियल एस्टेट,  
जयपुर।”

पढ़ें, “ 56. अध्यक्ष,

जयपुर इण्डस्ट्रियल एस्टेट एसोशियेशन,  
जयपुर।”

ओ० आर० पद्मनाभन, अवर सचिव

**कम्पनी कार्य विभाग**

नई दिल्ली-1, दिनांक 29 अप्रैल 1971

कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 209 की उप-धारा (4) के खंड (ख) के उपखंड (II) के अनुसरण में, कम्पनी विधि बोर्ड एतद्वारा भारत सरकार, कम्पनी कार्य विभाग के अधिकारी श्री बी० रामाराव, निरीक्षण अधिकारी कलकत्ता को, कथित धारा 209 के उद्देश्य के लिये प्रधिकृत करता है।

एम० के० वजर्जी, अवर सचिव

**स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय**

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 27 अप्रैल 1971

एफ० 14-10/69-जन स्वा० ई०—22 फरवरी 1971 के संकल्प संख्या एफ० 14-10/69—जन स्वा० ई० में देश की वायु दूषण नियंत्रण समिति के सदस्य—सचिव श्री जे० एम० दावे के पदनाम को संशोधित कर उसे केन्द्रीय जन स्वास्थ्य इंजीनियरी संगठन, निर्माण भवन, नई दिल्ली के सलाहकार (जन स्वा० ई०) पढ़ें।

**आदेश**

आदेश दिया जाता है कि इस संशोधन की एक-एक प्रतिलिपि निम्नांकित को भेज दी जाय :—

- (1) लोक सभा सचिवालय,
- (2) राज्य सभा सचिवालय
- (3) प्रधान मंत्री सचिवालय
- (4) मंत्री मण्डल सचिवालय
- (5) योजना आयोग
- (6) राष्ट्रपति के निजी एवं सैनिक सचिव
- (7) भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
- (8) भारत सरकार के सभी मंत्रालयों एवं विभागों

- (9) सभी राज्य सरकारें। संघ शासित प्रदेश  
(10) महा लेखाकार, केन्द्रीय राजस्व, नई दिल्ली  
(11) परमाणु विभाग  
(12) भारतीय चिकित्सा अनुसंधान, नई दिल्ली  
(13) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली  
(14) केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य इंजीनियरिंग अनुसंधान मंत्रालय, नागपुर  
(15) भाषा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, बम्बई  
(16) व्यावसायिक स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान, अहमदाबाद  
(17) केन्द्रीय श्रम संस्थान, बम्बई।  
(18) केन्द्रीय खनन अनुसंधान केन्द्र धनबाद  
(19) अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान तथा जन स्वास्थ्य संस्थान, कलकत्ता  
(20) केन्द्रीय जन स्वास्थ्य इंजीनियरिंग संगठन और स्वास्थ्य सेवाओं के महा निदेशक, नई दिल्ली।

आदेश दिया जाता है कि इस संशोधन को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाय।

अभिय भूषण मलिक, संयुक्त सचिव

**खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय  
(सहकारिता विभाग)**

नई दिल्ली, दिनांक 26 अप्रैल 1971

सं० एल०-12015/8/70-विबिध—भारत सरकार ने दिनांक 15 अक्तूबर, 1970 की अपनी अधिसूचना संख्या एल० 12015/8/70—विबिध में राष्ट्रीय सहकारी विकास नियम सम्बंधी एक विशेषण समिति स्थापित की थी। इस समिति द्वारा जिस अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट दी जाती है वह इससे द्वारा 30 सितम्बर, 1971 तक बढ़ाई जाती है।

**अदेश**

आदेश है कि इस अधिसूचना की प्रति विशेषण समिति के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों और दूसरे सभी संबंधियों को भेजी जाए।

यह भी आदेश है कि यह अधिसूचना सामान्य सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित की जाए।

ए० दास संयुक्त सचिव

**सिंचाई और विद्युत मंत्रालय**

नई दिल्ली, दिनांक अप्रैल 1971

**संदेश**

सं० ई० एल० तीन-12 (21)/61—दिल्ली ताप परियोजना नियंत्रण बोर्ड की स्थायी समिति के गठन से संबंधित इस मंत्रालय के संकल्प संख्या ई० एल०-दो०-12 (21)/61-जिल्द-III दिनांक 18 जुलाई 1969 में क्रय संख्या (V) पर वर्तमान प्रविष्टि के स्थान पर, निम्नलिखित को रखा जाए :

(V) संयुक्त सचिव (विद्युत) सिंचाई और विद्युत मंत्रालय

**आदेश**

आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प पंजाब और हरियाणा की सरकारों, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली नगर निगम, हरियाणा राज्य विजली बोर्ड, भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, प्रधानमंत्री सचिवालय, राष्ट्रीय केन्द्रीय, राज्य आयोग और भारत के महानियंत्रक तथा लेखापरीक्षक को भेजा दिया जाए।

यह आदेश भी दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

जी० जी० पटेल, सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 24 अप्रैल 1971

सं० बा० वि० 11 (58)/70—भारत सरकार, सिंचाई और विद्युत मंत्रालय के संकल्प सं० बा० वि० 11 (58)/70 दिनांक 11 जनवरी, 1971 के अधीन स्थापित किये गये उत्तर बंगाल बाढ़ नियंत्रण बोर्ड का पुनर्गठन निम्न प्रकार से किया जाता है :—

- |   |         |
|---|---------|
| 1. केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत संलग्न           | अध्यक्ष |
| 2. वित्त मंत्री सचिव मंत्रालय                   | सदस्य   |
| 3. कार्यकारी मंत्री, बाढ़-नियंत्रण पश्चिम बंगाल | सदस्य   |
| 4. कृषि मंत्री, पश्चिम बंगाल                    | सदस्य   |
| 5. बन मंत्री, पश्चिम बंगाल                      | सदस्य   |
| 6. अध्यक्ष, उत्तर बंगाल बाढ़ नियंत्रण आयोग      | सदस्य   |

2. बोर्ड की सहायता के लिए एक पूर्व-कार्यक सचिव होगा जिसकी नियुक्ति भारत सरकार के साथ परामर्श करके पश्चिम बंगाल सरकार करेगी। बोर्ड का मुख्यालय अलहाबाद/सिलिगुड़ी होगा।

3. बोर्ड एक उपाययोजन-आस्त सौति निधारक संस्था होगी और वह विभिन्न बाढ़ नियंत्रण स्कीमों की क्रियान्विति के लिए प्राथमिकताएं निश्चित करेगी। बोर्ड प्राकल्पनों को स्वीकृति प्रदान करेगा और धन के आवंटनों का अनुमोदन करेगा।

4. बोर्ड समय अपनी कार्य-नियमावली बनाएगा।

5. उत्तर बंगाल की नदियों के बाढ़ नियंत्रण के लिए व्यापक योजना तैयार करने और कार्यों की क्रियान्विति के लिए, पश्चिम बंगाल सरकार उत्तर बंगाल बाढ़ नियंत्रण आयोग नायक एक पूर्व-कार्यक संस्था स्थापित करेगी। उत्तर बंगाल बाढ़ नियंत्रण आयोग का अध्यक्ष पदेन उत्तर बंगाल बाढ़ नियंत्रण बोर्ड का एक सदस्य होगा। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत सरकार के साथ परामर्श करके राज्य सरकार करेगी।

6. पश्चिम बंगाल सरकार आयोग के काम का पुनरवलोकन करने तथा बाढ़ नियंत्रण स्कीमों के आयोजन, अभिकल्पन और क्रियान्वयन के दौरान उत्पन्न होने वाली समस्याओं के संबंध में

सलाह देने के लिए एक तकनीकी सलाहकर बोर्ड की भी स्थापना करेगी। इस बोर्ड के अध्यक्ष को उत्तर बंगाल बाढ़ नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष नामजद करेगा।

### आवेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रतिलिपि पश्चिम बंगाल सरकार/भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों/प्रधान मंत्री सचिवालय/राष्ट्रपति के निजी और सैनिक सचिव/भारत के महा-नियंत्रक तथा लेखापरीक्षक/योजना आयोग के पास सूचनार्थ भेज दी जाए।

यह आदेश भी दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया जाए और राज्य सरकार से अनुरोध किया जाए कि वे भी इसको आम सूचना के लिए राज्य के राजपत्र में प्रकाशित कर दें।

बी० एस० बंसल, संयुक्त सचिव

### श्रम, रोजगार और पुनर्वास मंत्रालय

#### (श्रम और रोजगार विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 27 अप्रैल 1971

### संकल्प

सं० 1/44/68-एम०-1—भारत सरकार को पत्थर-खान मालिकों के संघों से इस बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं कि खान अधिनियम, 1952 के क्षेत्र का विस्तार इतना व्यापक है कि लगभग सभी उत्खनन, जिनमें खुले कास्ट के काम सम्मिलित हैं, उसके क्षेत्र में आते हैं और यह कि इससे उन पत्थर खानों के खुले कास्ट में होने वाले कार्य में कठिनाई पैदा हो गई है जहाँ की कार्य-दशायें भूमि के नीचे की खानों की कार्य दशाओं से भिन्न हैं। आगे यह भी अभि-वेदन किया गया है कि खुले कास्ट वाली खानों के लिए एक अलग विधान होना चाहिए। भारत सरकार ने इन अभ्यावेदनों पर विचार किया है और उसका यह विचार है कि इस मामले की विस्तृत रूप से जांच करने की आवश्यकता है। तदनुसार इस मामले की जांच करने के लिए एतद्वारा एक विशेषज्ञ समिति, जिसका गठन और जिसके विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं, स्थापित की जाती है:—

#### 1. गठन

1. खान सुरक्षा के उप महानिदेशक, धनबाद पदेन अध्यक्ष  
खान तथा धातु
2. श्री आई० एम० आगा, खनन विभाग  
सलाहकार, खान तथा धातु विभाग, द्वारा मनोनीत सदस्य।  
नई दिल्ली।

3. श्री एस० एस० मंजरेकर, मसर्स कोयला खानों के  
टाटा आयरन एण्ड स्टील कं०, जम- अतिरिक्त खानों के

शेदपुर के सहायक महाअधीक्षक।

खुले कास्ट कार्य-स्थलों के मालिकों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य।

4. श्री बी० चौधरी, महा सचिव, कोयला खानों के  
जावार खान मजदूर संघ, 2, भट्टजी अतिरिक्त खुले कास्ट  
की बाड़ी, भूपालपुरा, उदयपुरा। कार्य स्थलों में नियो-  
जित श्रमिकों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य।

5. श्री डी० वी० एस. नारायण राव, गैर-सदस्य-सचिव।  
प्रवर विधि अधिकारी, खान सुरक्षा का महा निदेशालय, धनबाद।

#### 2. विचारार्थ विषय

(क) कोयला खानों के अतिरिक्त खानों के खुले कास्ट कार्य-स्थलों के प्रबन्धकों द्वारा खान अधिनियम, 1952 और उसके अधीन बनाये गये नियमों, विनियमों तथा उप-नियमों के उपबन्धों का अनुपालन करने में अनुभव होने वाली कठिनाइयों, यदि कोई हो, की जांच करना और उनके बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

(ख) इस बात की जांच करना कि क्या ऐसे कामों में श्रम तथा सुरक्षा के विनियम के लिए एक अलग विधान आवश्यक है और यदि हां तो खान अधिनियम, 1952 तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये नियमों, विनियमों व उप-नियमों में उसके परिणामस्वरूप आवश्यक परिवर्तनों के साथ एक विधान संबंधी योजना की सिफारिश करना।

2. समिति का मुख्यालय धनबाद में होगा।

3. समिति स्थापित होने के बाद अपनी रिपोर्ट छः माह की अवधि के अन्दर प्रस्तुत करेगी।

### आवेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों और सभी अन्य सम्बन्धियों को भेजी जाय।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प आम सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाय।

आई० डी० एन० साही, अतिरिक्त सचिव

**CABINET SECRETARIAT  
(Department of Personnel)**

*New Delhi, the 26th April 1971*

**CORRIGENDUM**

*No. F.32/20/70-Estt.(E).*—The following corrections shall be made in the Rules for Indian Economic Service/Indian Statistical Service (Released Emergency Commissioned/Short Service Commissioned Officers) Examination, 1971 published in Part I Section 1 of the Gazette of India, dated the 9th January, 1971 :—

*Reference*

*Correction to be made*

*Appendix II*

1. Page 65, col. 1, 2nd Sub-para of para 5 under heading "SECTION III General", line 6.

Add words "subjects, viz., Statistics I and Statistics II" and delete words "otherwise accruing to him".

*Schedule*

2. Page 65, col. 2, 5th sub-para of para 5, Statistics I—, last line.
3. Page 66, col. 2, first sub-para under PART 'B' *viva voce*, lines 6 & 7.

The word "polynomials" may be substituted for "polynomials".

The words "unbiated" and "examination" may read as "unbiased" and "examination".

*Appendix IV*

4. Page 67, col. 2, para 6(f). Night Blindness.—lines 4 and 10.
5. Page 68, col. 2, para 10(b).
6. Page 68, col. 2, para 12, lines 17-18.
7. Page 69, col. 1, 8th sub-para under heading "Medical Board's Report", line 3.
8. Page 69, col. 1, item 2(a) of "Candidate's statement and declaration" under the heading "Medical Board's Report", line 8.
9. Page 69, col. 1, item 5 of "candidate's Statement and declaration" under heading "Medical Board's Report", line 3.

The words "Retinitis" and "fall" may be read as "Retinitis" and "fall".

The word "implement" may be read as "impediment".

The words "Cabinet Secretariat" may be added before the words "Department of Personnel".

The word "in" printed between the words "communicated" and "the candidate" may be read as "to".

The letter "s" before the word "Yes" may be read as "is".

The word "of" may be read as "or".

K. V. MAHALINGAM, Under Secy.

*New Delhi-1, the 29th April 1971*

**CORRIGENDUM**

*No. 20/1/71-AIS(I).*—In the Department of Personnel Notification No. 20/1/71-AIS(I), dated the 6th March, 1971, published in Part I, Section 1 of the Gazette of India of the 6th March, 1971, the following under sub-rule (2) of Rule 6 of the Rules for the Combined Competitive Examination, 1971 may be deleted :—

Certificate of eligibility will not, however, be necessary in the case of candidates belonging to any one of the following categories :—

- (i) Persons who migrated to India from Pakistan before the nineteenth day of July, 1948, and have ordinarily been residing in India since then.
- (ii) Persons who migrated to India from Pakistan on or after the nineteenth day of July, 1948, and have got themselves registered as citizens under Article 6 of the Constitution.
- (iii) Non-citizens in Category (f) above who entered service under the Government of India before the commencement of the Constitution, viz., 26th January, 1950, and who have continued in such service since then. Any such person who re-entered or may re-enter such service with break after the 26th January, 1950, will however, require certificate of eligibility in the usual way.

B. NARASIMHAN, Under Secy.

**PLANNING COMMISSION**

*New Delhi, the 23rd April 1971*

**RESOLUTION**

*Standing Review Committee for Additional Excise Duties*

*No. F.3/5/70-CDN.*—The Fifth Finance Commission recommended that it would not be desirable to maintain the existing arrangements in respect of additional excise duties in Lieu of State sales tax on sugar, tobacco and

mill-made textiles unless the Government of India after discussing the matter further with the State Governments can arrive at a general agreement for the continuance of the present arrangements with suitable modifications. In pursuance of this recommendation, the subject, after being duly considered by the officials of the State Governments, Union Territories and concerned Union Ministries, was placed before the Committee of the National Development Council at its meeting held in Delhi on 28th December, 1970. The Committee agreed on a new arrangement for imparting elasticity to the revenue from additional excise duties. It also recommended that a Standing Review Committee should be set up by the Planning Commission to review periodically the working of, and suggest improvements, in the new arrangement for additional excise duties.

2. The Planning Commission have, therefore, decided to appoint a Standing Review Committee. The Committee will consist of :—

*Convenor*

- (1) Economic Adviser, Planning Commission.

*Members*

- (2) Member (Tariff) Central Board of Excise and Customs, Ministry of Finance, Department of Revenue and Insurance.
- (3) Economic Adviser, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs.
- (4) Financial Commissioner or Secretary who is, for the time being, in charge of Sales Tax in each of the States.

3. The terms of reference of the Committee will be as follows :—

To review the working of the new arrangement for additional excise duties, as a whole, and to make such recommendations as may be necessary for its improvement.

4. The headquarters of the Standing Review Committee shall be in New Delhi.

5. The Standing Review Committee shall meet at least once a year.

## ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all State Governments, Union Territories, all Ministries of the Government of India, the Prime Minister's Secretariat, Secretary to the President, and Secretary to the Vice-President.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India.

A. MITRA, Secy.

# MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT AND INTERNAL TRADE

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 30th April 1971

## RESOLUTION

No. SSI(B)-10(3)/68.—In their Office Memorandum No. SSI(B)-10(30)/68, dated the 22nd September, 1968 the Government of India in the late Ministry of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Department of Industrial Development) constituted a Committee, under the Chairmanship of Shri N. J. Kamath, Joint Secretary, to review and evaluate the activities of the Inventions Promotion Board, to determine to what extent it has helped in promoting the objectives for which the Board was established and to recommend measures that are considered necessary for the fulfilment of the objectives of the Board, with particular emphasis on the small scale sector.

2. The Committee in its report submitted on 16-4-70 has made a number of recommendations of which the more important are the following:

- (i) The Inventions Promotion Board may continue to function as an autonomous Organisation under the control of the Ministry of Industrial Development and Internal Trade.
- (ii) To ensure greater control in financial and operational matters in the running of the Board, the Vice-President of the Board (who is also the representative of the Ministry of Industrial Development) might be delegated with powers to guide the Executive Director in administrative matters.
- (iii) A compact Business Committee, presided over by the Vice-President of the Board may be constituted to advise the Executive Director.
- (iv) The working of the IPE should be reoriented so as to have a greater impact on rural problems. Financial assistance and prize awards given by the Board should be available in a greater measure to independent inventors, artisans and technicians.
- (v) A well-equipped patent Information Centre to assist inventors to draw patent specifications may be operated by the Board.

3. After careful consideration, and taking note of the changes that have already been effected in the working of the Board since the submission of the report, Government accept all the recommendations made by the Committee subject to the following.

(i) *Recommendation No. 2*

- (a) The President, if he considers necessary, delegate such administrative powers to the Vice-President as may be considered desirable and necessary for the better functioning of the Board.
- (b) Government also desire that greater attention be paid by the Board to follow-up of the Inventions for which assistance has given by the IPB. In this respect, the Board may work in closer co-operation with other concerned agencies of Government.

4. Government also wish to place on record their appreciation of the work rendered by the Committee, headed by Shri N. J. Kamath in making a thorough study and evaluation of the working of the IPB.

## ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to all concerned.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India, for general information.

B. B. IAL, Secy.

New Delhi, the 3rd May 1971

No. SSI(A)-17(3)/70.—In the Ministry of Industrial Development & Internal Trade Resolution No. SSI(A)-17(3)/70, dated the 25th August, 1970, under which the Small Scale Industries Board was reconstituted, the following amendment may be made in the list of members of the Board:—

For "56. President, Rajasthan Industrial Estate Manufacturers Association, 40, Industrial Estate, Jaipur."

Read "56. The President, Jaipur Industrial Estate Association Jaipur."

O. R. PADMANABHAN, Under Secy.

## DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS

(Company Law Board)

New Delhi-1, the 29th April 1971

## ORDER

No. SSI(1)/70-CH.—In pursuance of sub-clause (ii) of Clause (b) sub-section (4) of Section 209 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) the Company Law Board hereby authorises Sri V. Rama Rao, inspecting Officer, Calcutta an officer of the Government of India, Department of Company Affairs for the purposes of the said Section 209.

M. K. BANERJEE, Under Secy.

## MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY PLANNING

(Department of Health)

New Delhi, the 27th April 1971

No. F.14-10/69-PHE.—In the Resolution No. F.14-10/69-PHE, dated the 22nd February, 1971, the designation of Shri J. M. Dave, Member-Secretary of the Committee on Air Pollution Control in the Country may be amended to read as Adviser (PHE), Central Public Health Engineering Organisation, Nirman Bhawan, New Delhi.

## ORDER

ORDERED that this Amendment be communicated to:—

- (i) Lok Sabha Secretariat.
- (ii) Rajya Sabha Secretariat.
- (iii) Prime Minister's Secretariat.
- (iv) Cabinet Secretariat.
- (v) Planning Commission.
- (vi) Private and Military Secretaries, to the President.
- (vii) Comptroller and Auditor General of India.
- (viii) All Ministries and Departments of the Government of India.
- (ix) All the State Governments/Union Territories.
- (x) A.G.C.R., New Delhi.
- (xi) Department of Atomic Affairs.
- (xii) Indian Council of Medical Research, New Delhi.
- (xiii) Council of Scientific and Industrial Research, New Delhi.
- (xiv) Central Public Health Engineering Research Institute, Nagpur.
- (xv) Bhabha Atomic Research Centre, Bombay.
- (xvi) Occupational Health Research Institute, Ahmedabad.
- (xvii) Central Labour Institute, Bombay.
- (xviii) Central Mining Research Centre, Dhanbad.
- (xix) All India Institute of Hygiene and Public Health, Calcutta.
- (xx) Central Public Health Engineering Organisation; and
- (xxi) Director General of Health Services, New Delhi.

ORDERED that the Amendment be published in the Gazette of India.

A. B. MALIK, Jt. Secy.



**MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY  
DEVELOPMENT & COOPERATION**

(Department of Agriculture)

(I.C.A.R.)

*New Delhi, the 7th April 1971***RESOLUTION**

No. 3(2)/69-ASII/FCII.—In partial modification of the Ministry of Food and Agriculture C.D. & Cooperation (Department of Agriculture) (ICAR) Resolution No. 3(2)/69-ASII/FCII, dated 11th August, 1970 Government has decided that the time limit for presenting the report by the High Level National Scientific Committee on Plant introduction and Quarantine to Government is extended for a period of three months with effect from 11th February, 1971.

**ORDER**

ORDERED that a copy of the Resolution be forwarded to the chairman and members of the high level National Scientific committee. All Ministries/Deptt. of the Government of India, the P.M. Secretariat, the president secretariat, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Comptroller and Auditor General of India, Revenue Secretaries to the State Government/U.T., the Rajya Sabha/Lok Sabha Sec'tt. and Parliament Library.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India.

K. P. A. MENON, Jt. Secy.

(Department of Cooperation)

*New Delhi, the 26th April 1971***RESOLUTION**

No. L.12015/8/70-Misc.—The Government of India, in their Notification No. L.12015/8/70-Misc., dated the 15th October, 1970 had set up an Expert Committee on the National Cooperative Development Corporation. The period within which this Committee shall submit its report is hereby extended up to the 30th September, 1971.

**ORDER**

ORDERED that a copy of the notification be communicated to the Chairman and other members of the Expert Committee and all others concerned.

ORDERED also that the notification be published in the Gazette of India for general information.

A. DAS, Jt. Secy.

**MINISTRY OF IRRIGATION AND POWER***New Delhi, the 24th April 1971***RESOLUTION**

No. F.C.II(58)/70.—The North Bengal Flood Control Board set up under Government of India, Ministry of Irrigation & Power, Resolution No. F.C.II(58)/70, dated the 11th January, 1971, is reconstituted as follows:—

*Chairman*

1. Union Minister of Irrigation and Power.

*Members*

2. Minister of Finance, West Bengal.
3. Minister incharge of Flood Control, West Bengal.
4. Minister of Agriculture, West Bengal.
5. Minister of Forest, West Bengal.
6. Chairman, North Bengal Flood Control Commission.

2. The Board will be assisted by a whole-time Secretary to be appointed by the Government of West Bengal in consultation with the Government of India. The headquarters of the Board will be situated at Jalpaiguri/Siliguri.

3. The Board will be a high-powered policy making body and will decide priorities in the implementation of the various flood control schemes. The Board will accord sanction to estimates and approve the allocation of funds.

4. The Board will frame its own rules of business.

5. For preparing a comprehensive plan for flood control of the North Bengal rivers and for execution of works, the West Bengal Government will set up a whole time organisation viz. North Bengal Flood Control Commission. The Chairman of the North Bengal Flood Control Commission will be an *ex-officio* Member of the North Bengal Flood Control Board. The Chairman and Members of the Commission will be appointed by the State Government in consultation with the Government of India.

6. The Government of West Bengal will also set up a Board of Technical Consultants to review the work of the Commission and to advise on the problems that may arise during planning, design and execution of flood control schemes. The Chairman of this Board will be nominated by the Chairman of the North Bengal Flood Control Board.

**ORDER**

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to the State Government of West Bengal/concerned Ministries of the Government of India/Prime Minister's Secretariat/Private and Military Secretary to the President/Comptroller and Auditor General of India/Planning Commission for information.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India and that the State Government be requested to publish it in the State Gazette for general information.

B. S. BANSAL, Jt. Secy.

**MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT &****REHABILITATION**

(Department of Labour &amp; Employment)

*New Delhi, the 27th April 1971***RESOLUTION**

No. 1/14/68-MH.—The Government of India have received representations from Associations of stone quarry owners to the effect that the coverage of the Mines Act, 1952 is so wide that almost all excavations, including open cast workings, are covered and that this has created difficulty in the working of the open cast quarries where the working conditions differ from those in underground mines. It has, further, been represented that there should be a separate legislation for open cast quarries. The Government of India have considered the representations and are of the view that the matter requires detailed examination. Accordingly, an Expert Committee, with the following composition and terms of reference, is hereby set up to go into the matter:—

**I. Composition**

- (1) Deputy Director General of Mines Safety, Dhanbad—*Ex-officio* Chairman.
- (2) Shri I. M. Aga, Mining Adviser, Department of Mines and Metals, New Delhi—Member nominated by the department of Mines and Metals.
- (3) Shri S. S. Manjrekar, Assistant General Superintendent of Mines of Messrs Tata Iron and Steel Co., Jamshedpur—Member to represent the interest of owners of open cast workings other than coal mines.
- (4) Shri B. Chaudhury, General Secretary, Zawar Mines Mazdoor Sangh, 2, Bhattji-ki-Bari, Bhupal-pura, Udaipur—Member to represent the interest of the workers employed in open cast workings other than coal mine.
- (5) Shri D. V. S. Narayana Rao, Senior Law Officer, Directorate General of Mines Safety, Dhanbad—non member Secretary.

**II. Terms of reference**

- (a) to examine and report on the difficulties, if any, in the compliance by managements of open cast workings, in mines other than coal mines, with the provision of the Mines Act, 1952 and the Rules, Regulations and bye-laws made thereunder;

- (b) to examine whether a separate legislation is necessary for the regulation of labour and safety in such workings and, if so, to recommend a scheme of legislation, together with the consequential changes that will be necessary in the Mines Act, 1952 and the rules, regulations and bye-laws made thereunder.

2. The headquarters of the Committee will be at Dhanbad.

3. The Committee will submit its report within a period of six months after it has been set up.

#### ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to the Ministries/Departments of the Government of India, State Governments/Administrations of Union Territories and all others concerned.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

I. D. N. SAHL, Addl. Secy.